पाकिस्तान–बांग्लादेश सीमा होगी अभेद्य

घुसपैठ रोकने को दोनों सीमाओं पर एक वर्ष के भीतर लागू होगा 'स्मार्ट बार्डर प्रोजेक्ट' : शाह

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- गृह मंत्री ने कहा– ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरों के साथ आधुनिक तकनीक से लैस होगी 6000 किमी लंबी सीमा
- सीमांत क्षेत्रों की जन सांख्यिकी को बदलने की साजिश भी होगी विफल

घुसपैठ और तस्करी जैसी दशकों पुरानी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती 6000 किलोमीटर लंबी सीमा को ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरों व तकनीक के सहारे अभेद्य बनाने जा रही है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक वर्ष में "नई बार्डर स्ट्रेटेजी" के तहत "स्मार्ट बार्डर प्रोजेक्ट" शुरू करने की घोषणा की।

पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संस्थापक के.एफ. रुस्तमजी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, सीमांत इलाकों में जनसांख्यिकी परिवर्तन से निपटने के लिए प्रस्तावित उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन का जल्द गठन किया जाएगा। पीएम नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से इस मिशन के गठन का एलान किया था। 'जागरण ब्यूरो' के अनुसार गृह मंत्री ने बताया कि "स्मार्ट बार्डर प्रोजेक्ट" के तहत सीमा पर "तकनीक आधारित स्मार्ट सिक्योरिटी ग्रिड" खड़ी करने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमांत इलाकों में असामान्य तरीके से जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं होने देंगे और एक-एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। त्रिपुरा व असम के बाद अब बंगाल में भी ऐसी सरकार आ गई है, जो घुसपैठ रोकने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने बीएसएफ को इनके साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। शाह ने बीएसएफ को सीमा की सुरक्षा को अलग करके देखने के बजाय समेकित तरीके से देखने का निर्देश दिया। कहा, केंद्रीय बल जिला प्रशासन, पुलिस थानों, पंचायतों और पटवारियों के साथ मिलकर घुसपैठ को बंद करे। शाह के अनुसार, सीमा की सुरक्षा को सिर्फ ड्यूटी मानने के बजाय, उस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। सीमा से अवैध घुसपैठ के साथ ही ड्रग्स, तस्करी, गौ-तस्करी, नकली करेंसी की तस्करी और संगठित अपराध की चुनौतियां हैं। ड्रोन से हथियारों की तस्करी ने इन खतरों को बढ़ा दिया है। इन सभी समस्याओं से बीएसएफ अकेले नहीं निपट सकती। इसके लिए बीएसएफ को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राज्य पुलिस, अन्य अर्धसैनिक बलों और खुफिया ब्यूरो के साथ मिलकर काम करना होगा।

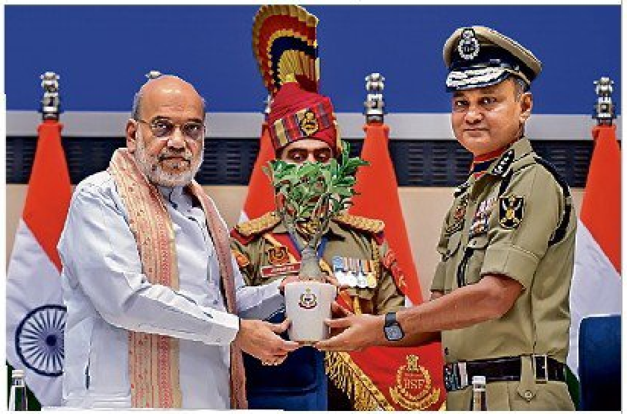

नई दिल्ली में शुक्रवार को के.एफ.रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को सम्मानित करते बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार। एएनआइ

कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलाव रोकने को सतर्क रहना होगा

प्रेट्र के अनुसार, सुरक्षा के नजरिये से इन दोनों सीमाओं को संवेदनशील व देश के लिए चिंता का कारण बताते हुए शाह ने कहा, इन मोर्चों की सुरक्षा पारंपरिक तरीकों से नहीं की जा सकती। भविष्य के खतरों की पहचान करना सबसे जरूरी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि घुसपैठ के जरिये सीमा पार से से किए जा रहे कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों को रोकें। इसके लिए हमें सतर्क और चौकस रहना होगा।

मोदी सरकार ने सुरक्षा नीति और सीमा की सुरक्षा के नजरिये में बड़ा बदलाव किया है

अमित शाह ने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी सरकार ने सुरक्षा नीति और सीमा सुरक्षा के नजरिये में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा, "हमने पाकिस्तान को तीनों हमलों में पराजित किया है, चाहे वह उरी (2016) में हुआ हो, पुलवामा (2019) में, या पहलगाम (2026) में... हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है।" शाह ने कहा, अब वो दिन गए जब किसी आतंकी हमले के बाद बातचीत होती थी और जब माओवादी बिना किसी खौफ के नरसंहार करते थे। हमने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण को संविधान की भावना के अनुरूप ढाला है ताकि इसे मजबूत बनाया जा सके... यह सब एक तरह से नए रक्षा सिद्धांत की घोषणा है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत को माओवाद से मुक्त कराने का एक "दृढ" फैसला लिया था और हाल ही में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। उनका मानना है कि सुरक्षा एजेंसियों और बलों को समस्या की जड़ को "खत्म" करने के लिए काम करना चाहिए, न कि उसे सिर्फ "नियंत्रित" करने के लिए। शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार अगले एक वर्ष के भीतर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के जवानों के कल्याण के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही सरकार देश में नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध भी एक बड़ा अभियान शुरू करेगी। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों को वीरता पदकों से सम्मानित किया। इनमें वे अधिकारी व जवान भी शामिल थे जो 'आपरेशन सिंदूर' का हिस्सा थे।

बंगाल की खाड़ी • तीन करार से अमेरिका की एंट्री, मलक्का तक हो सकेगी निगरानी

बांग्लादेश ने अमेरिकी युद्धपोतों को सौंपे 2 बंदरगाह, खुफिया सूचना भी साझा करेंगे

ढाका से भास्कर संवाददाता
अमानुर रहमान

बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने एंट्री ले ली है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए तीन करार से यह संभव हो रहा है। पहला व्यापार समझौता 'आर्ट' (एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड) है, जबकि दो करार (अक्सा और जिसोमिया) रक्षा से जुड़े हैं। इन्हीं करारों के जरिए अमेरिका को बांग्लादेश के दो रणनीतिक बंदरगाहों, चटगांव और मतारबाड़ी तक सैन्य पहुंच का रास्ता खुल रहा है। अक्सा लागू होने के बाद अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और सैन्य विमान इन बंदरगाहों का इस्तेमाल रसद, ईंधन भरने, मरम्मत, रखरखाव और सैनिकों की आवाजाही के लिए कर सकेंगे।

दूसरी ओर, जिसोमिया के तहत दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोपनीय सैन्य और खुफिया सूचनाएं साझा करने की व्यवस्था बनेगी। इसका मतलब है कि बांग्लादेश सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका के इंडो-पैसिफिक सैन्य ढांचे का अहम पड़ाव बन सकता है।

मलक्का पर अमेरिका की नजर... क्योंकि 60% वर्ल्ड ट्रेड इसी रूट से

- स्ट्रेट ऑफ मलक्का हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग व चोकपॉइंट है। दुनिया का 60% ट्रेड यहीं से गुजरता है, इसी वजह से अमेरिका की नजर इस पर है।
- चटगांव व मतारबाड़ी में पहुंच से अमेरिका बंगाल की खाड़ी से मलक्का तक जाने वाले समुद्री रुट पर निगरानी, रसद व सैन्य पहुंच मजबूत कर सकेगा। इससे चीन की मलक्का दुविधा और बढ़ेगी।
- वैश्विक व्यापार के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि अगर यह क्षेत्र सैन्य प्रतिस्पर्धा का मैदान बना, तो तेल, गैस, कंटेनर शिपिंग, बीमा और सप्लाई चेन सभी महंगे और अस्थिर हो सकते हैं।

चिंता... त्रिपुरा से 80 किमी दूर है मतारबाड़ी बंदरगाह

चटगांव और मतारबाड़ी बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में हैं। त्रिपुरा के सबरूम क्षेत्र से चटगांव 80 किमी तो मतारबाड़ी 150 किमी दूर है। इन बंदरगाहों पर अमेरिकी आवाजाही से उनकी नौसेना भारत के पूर्वोत्तर के पास ज्यादा देर तक ठिकाना बनाएगी और अंडमान सागर तक निगरानी मजबूत कर सकेगी।

धमकी... टैरिफ छूट बचाए रखने के लिए हुआ करार

बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था गारमेंट्स पर टिकी है। अमेरिका ने इसी कमजोरी को दबाव का औजार बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सीधे संकेत दिया कि रक्षा समझौते नहीं हुए तो बांग्लादेश को मिल रहे 19% टैरिफ रियायत व ड्यूटी-फ्री कोटा खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश ने इसी दबाव में आकर करार किए हैं।

इधर... पाक ने बांग्लादेश को दिए दो जेएफ-17 जेट

पाकिस्तान ने बांग्लादेश एयरफोर्स को दो जेएफ-17 फाइटर जेट सिमुलेटर सौंपे हैं। ये बांग्लादेशी पायलटों की ट्रेनिंग व एयरक्राफ्ट ऑपरेशन की तैयारी के लिए दिए गए हैं। जेएफ-17 विमान पाक-चीन ने मिलकर विकसित किया है। बांग्लादेश एयरफोर्स की ट्रेनिंग हो जाने के बाद पाक इसकी खेप उन्हें तीन माह बाद सौंपेगा।

भारत और साइप्रस के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व साइप्रस के राष्ट्रपति निकोसक्रिस्टोडुलिड्स की बैठक में फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिड्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें दोनों देशों ने भारत-साइप्रस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का एलान किया। यूरोपीय संघ (ईयू) का समुद्री द्वार समझे जाने वाला साइप्रस ईयू का छठा देश है जिसके साथ भारत ने अपने संबंधों को यह दर्जा दिया है। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध व व्यापार सहयोग को नई गति देने के लिए संयुक्त कार्यबल गठित करने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में मोदी ने कहा, 'पिछले दशक में साइप्रस से भारत में निवेश करीब दोगुना हो चुका है। हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इसे पुनः दोगुना करना है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देकर ऊंचा उठा रहे हैं।'

मोदी ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को 'मजबूत व भविष्योन्मुखी'बताया। कहा, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के बाद साइप्रस के माध्यम से व्यापार, निवेश व आर्थिक सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया संकट और यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने यूएन, यूएनएससी आदि में सुधार पर भी एकमत व्यक्त किया और कहा ,बढ़ती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यह सुधार अत्यंत जरूरी हैं। यह रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय हुई है जब तुर्किये, पाकिस्तान संग रक्षा व सैन्य संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। गत वर्ष आपरेशन सिंदूर में तुर्किये ने पाक को पूरा समर्थन दिया था। दूसरी तरफ साइप्रस लंबे समय से तुर्किये के साथ क्षेत्रीय विवाद और तनाव में फंसा है। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत-साइप्रस के संबंध किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं हैं। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग का एक रोडमैप बना रहे हैं। साइप्रस का भारत के लिए विशेष सामरिक महत्व है क्योंकि यह यूरोप का समुद्री द्वार माना जाता है। साइप्रस के राष्ट्रपति की तीन दिनी भारत यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संतुलन और बहुआयामी साझेदारी को नई दिशा दे सकती है। मोदी ने वर्ष 2025 में साइप्रस की यात्रा की थी। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों में प्रगति हुई है।

नई दिल्ली में शुक्रवार को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिड्स के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएनआइ

भारत ने कहा, साइप्रस के साथ संबंध किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं

छह समझौतों पर हस्ताक्षरः प्रेट्र के अनुसार, दोनों देशों ने नवाचार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्रों में गहरा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही प्रवासन व आवाजाही पर जल्द ही व्यापक साझेदारी को अंतिम रूप देने पर भी सहमति व्यक्त की। इन समझौतों में से एक आतंकवाद-रोधी उपायों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने से संबंधित है। दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचा, जहाजरानी व आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए भी संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है। क्रिस्टोडुलिड्स ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आइएमईईसी) की सराहना की और कहा कि तीन महाद्वीपों के संगम और यूरोप के प्रवेश द्वार पर स्थित साइप्रस इसमें सक्रिय योगदान देने को तैयार है। साइप्रस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन जारी रखेगा। साथ ही मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलेगा।

तुषार दहिया के बाद मां परवीन रानी भी बनीं मेयर, रचा इतिहास

हरीश भौरिया • जागरण

- तुषार एल्सट्री और बोरेहामवुड के मेयर बने थे, अब मां परवीन हट्र्समेयर बरो की बनीं मेयर
- ब्रिटेन में भारतीय मूल की मां-बेटे की जोड़ी ने दो अलग-अलग शहरों में मेयर बनकर बनाया रिकार्ड

सोनीपत : ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक परिवार ने राजनीतिक क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। सोनीपत के रोहणा गांव के तुषार दहिया पिछले सप्ताह ब्रिटेन के एल्सट्री और बोरेहामवुड के मेयर बने थे, वहीं 20 मई को उनकी मां परवीन रानी हट्र्समेयर बरो काउंसिल की मेयर बनकर कीर्तिमान रचने में कामयाब रहीं। परवीन रके पति सुनील दहिया का कहना है कि यूके के इतिहास में कभी कोई मां-बेटा ऐसा नहीं कर पाए हैं। इस उपलब्धि को न केवल ब्रिटेन बल्कि वैश्विक भारतीय समुदाय के लिए भी गर्व का पल माना जा रहा है।

13 मई को 23 वर्षीय तुषार दहिया ब्रिटेन में भारतीय मूल के सबसे युवा मेयर बने थे। उनकी मां परवीन रानी ने भी मेयर बनकर इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बनाने का काम किया है। परवीन 2013 में 10 वर्षीय तुषार को लेकर ब्रिटेन में रहने लगी थीं। वहां पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू किया और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी दर्ज करने के लिए धर्मार्थ संगठन हिंदी शिक्षा परिषद के जरिए वहां बसे भारतीय मूल के परिवारों के बच्चों को हिंदी पढ़ाना शुरू किया।

मेयर बनी परवीन रानी अपने बेटे मेयर तुषार दहिया के साथ। स्वजन

Birth rate, infant deaths fall in India, finds survey

Ramya Kannan
CHENNAI

The bulletin from the recent Sample Registration Survey (SRS) 2024 provides the sharpest picture yet of India in the throes of demographic transition.

As per the latest estimate, while the country's birth rate has fallen between 2014 and 2024 and the death rate is down marginally, good gains have been reported with the Infant Mortality Rate (IMR), amid substantial progress made over the last decade. However, vast gaps persist between rural and urban areas and progress across the country is uneven, making the call for equitable growth and appropriate deployment of resources particularly sound.

Changing trends

India's birth rate, death rate and infant mortality rate have fallen over the last decade, though vast rural-urban gaps and uneven progress persist

Indicator	2014	2024	Difference
Birth rate	21	18.3*	Down by 2.7 points
Death rate	6.7	6.4**	Down by 0.3 points
Infant mortality rate	39	24#	Down by 15 points

■ Kerala has a single-digit IMR of 8, the lowest in the country

*Births per population of 1,000

**Deaths per population of 1,000

Infant deaths per 1,000 live births

Source: SRS Bulletin 2024

The country's birth rate – live births per 1,000 population – fell from 21 in 2014 to 18.3 in 2024, while the death rate (deaths per 1,000 people) is down from 6.7 to 6.4. The IMR, recorded as the number of deaths per thousand live births, has dropped from 39 to 24. While the overall performance is creditable, indicating several measures being launched by the Centre and States to improve healthcare outcomes, the disappointment is in the relatively worse performance in rural areas. In fact, they drag the country's averages down substantially.

For instance, while the rural birth rate fell from 22.7 to 20.2 in the given decade, the simultaneous decadal performance in the urban areas was better – the birth rate fell from 17.4 to 14.7. In the rural areas, the death rate fell from 7.3 to 6.8 between 2014 and 2024, and in the urban segment, it was at 5.5 in 2014 and went up marginally to 5.6 – still a better performance than in rural areas.

The gains of urban areas in this bulletin are probably the most appreciable result in the field of IMR, dropping from 26 to 17 by nine points. While it has dropped 16 points from 43 to 27 in the rural areas during the same period, it is still further away from the national target to reduce the IMR to single digits.

The differences are also stark, with some States way ahead of the rest. Kerala and Tamil Nadu lead the way with better statistics in all sectors. Kerala has the lowest natural growth rate (NGR) of 3.9, the rate at which a population increases or decreases due to births and deaths, excluding migration, expressed as a percentage. It is also a crucial indicator of demographic transition.

Kerala also has a single-digit IMR (8), the lowest in the country. Tamil Nadu brings up the second position among larger States, with an NGR of 4.8 and an IMR of 11. Among the smaller States, Goa (4.2 NGR and 11 IMR) and among Union Territories, Andaman and Nicobar Islands (4.1 NGR and 9 IMR) show the way.

Interpreting the 'rise' of the Cockroach Janta Party

In just four days, a formation in India calling itself the 'Cockroach Janta Party' has accumulated a following that established political organisations often spend years building. Meme pages, Instagram reels, and semi-ironic political formations began aggregating at remarkable speed, prompting comparisons with Bangladesh and Nepal, where youth-led mobilisations appeared capable of unsettling entrenched political arrangements through digitally synchronised anger. Increasingly, many are wondering whether this is the future of politics itself: reactive and emotionally charged, and organised less around long-term political structures than around symbolic enemies and collective outrage.

The excitement is understandable because younger people increasingly feel disconnected from institutional politics and representative structures that appear distant from their lived anxieties about work, aspiration, insecurity, and exhaustion. Social media allows individuals who otherwise experience themselves as politically isolated to suddenly participate in moments of collective emotional intensity. A meme or slogan can create the feeling of political participation within hours. Yet, the deeper question is whether politics organised primarily through synchronised outrage can sustain itself beyond moments of emotional intensity.

The erosion of collective social life

The real crisis is not simply institutional decline or ideological exhaustion. The deeper crisis concerns the erosion of collective social life itself. Public life has weakened, and many shared spaces through which people once experienced collective belonging have steadily deteriorated. In the past, political formations emerged through unions, campuses, neighbourhood associations, and everyday cultures of participation embedded within ordinary social life. Those structures created continuity and emotional investment that allowed political life to exist beyond immediate reaction. Increasingly, however, societies produce individualised subjects who remain emotionally hungry for collective belonging while lacking the social conditions that are necessary to sustain it.

Perhaps this reflects one of the deeper contradictions of modernity itself. The language of liberty that emerged after the French Revolution was historically tied to emancipation and collective self-rule. Yet, over time, especially within consumer societies shaped by fossil-fuel-driven development, freedom increasingly came to mean individualised freedom of choice: the freedom to consume, compete, and privately pursue aspiration. Public life gradually weakened as private life expanded.

Soumyajit Bhar

Senior Assistant Professor at the School of Liberal Studies, BML Munjal University

Digital political mobilisation also reflects fragmentation beneath contemporary public and social life

Under such conditions, digitally synchronised crowds become psychologically powerful because they temporarily relieve isolation. A common enemy allows fragmented individuals to feel collectively present again.

This is where the distinction between synchronisation and solidarity becomes important. Contemporary platforms are extraordinarily effective at producing synchronisation. Millions can feel emotionally aligned within hours through shared outrage or a symbolic target. However, emotional synchronisation is not the same as durable collective life. One produces intensity; the other requires continuity, memory, emotional investment, and long-term commitment. Contemporary politics increasingly forms around antagonism rather than shared futures because outrage circulates faster than organisation, and anger is easier to sustain digitally than commitment.

Cross-country comparisons require caution

This is why comparisons with Bangladesh and Nepal require caution. The underlying conditions do not appear fundamentally different. In both cases, initial reactive energy eventually moved toward more organised political formations. The decentralised swarm did not remain decentralised; it was redirected, institutionalised, or exhausted. That suggests the deeper issue may not concern student politics or youth mobilisation in one country versus another. The broader structural tendencies – individualisation, fragmented public life, and weakening collective institutions – increasingly appear shared across much of the contemporary world.

This is where reflections emerging from the recent Iran-Israel-United States tensions become relevant. Decentralised resilience is only possible when sustained by deeper emotional and material structures capable of surviving beyond moments of immediate confrontation. Distributed action cannot function indefinitely through outrage alone. For decentralised systems to remain coherent without centralised command at every stage, there must exist some larger shared horizon: collective ethical commitment, emotional continuity, historical memory, or durable symbolic attachment. Decentralisation is not merely organisational or technological; it is also emotional, cultural, and material.

What increasingly appears visible in contemporary digital politics is the coexistence of enormous emotional energy with weakening structures of collective endurance. This is where Jacques Lacan's famous intervention during the May 1968 French student uprisings becomes relevant. At a moment when many intellectuals imagined the protests as radically emancipatory, Lacan responded with an unsettling observation: "What you aspire to as revolutionaries is a master. You will get one." His point was not merely cynical. Revolt against one symbolic order does not automatically abolish mastery. More often, desire reorganises itself around new forms of certainty and authority.

This insight becomes important in societies shaped by individualised aspiration and emotional fragmentation because politics organised primarily through opposition derives much of its coherence from the enemy itself. The enemy stabilises identity and keeps the crowd emotionally synchronised. But once movements move toward governance, contradictions emerge, compromises become necessary, and symbolic clarity weakens. The crowd that formed around shared antagonism then discovers that sustaining a collective world is far more difficult than synchronising anger.

There is also a deeper material contradiction. Developmental systems shaped by fossil-fuel-driven modernisation not only intensify individualisation but also structurally reproduce centralisation. Energy systems, logistics networks, financial architectures, digital platforms, and megacities all operate through immense concentrations of coordination and power. Even the platforms through which decentralised political energies circulate are themselves among the most centralised technological systems in history.

The central point

This creates a contradiction at the heart of contemporary anti-establishment politics. People increasingly desire decentralisation emotionally while inhabiting systems structurally dependent on centralisation. The crowd can challenge power, but reorganising power requires engagement with material systems that push relentlessly toward concentration, scale, and control. Unless societies can begin rebuilding the emotional, institutional, and material foundations necessary for collective life – trust, shared responsibility, organisational memory, and durable public commitment – reactive synchronisation will continue to reproduce cycles of outrage without durable transformation.

The central question is not whether decentralised political energy can emerge. It clearly can. The real question is whether contemporary societies still possess the capacity to transform synchronisation into solidarity, and moments of reactive mobilisation into enduring collective forms, or whether every rupture will eventually reproduce new concentrations of power and, as Lacan warned, new masters.

India, Cyprus elevate bilateral ties to strategic partnership; ink pact for defence cooperation

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

In a sign of India's expanding involvement in the eastern Mediterranean region, Prime Minister Narendra Modi on Friday said that India's ties with Cyprus are based on "respect for sovereignty and territorial integrity".

Welcoming Cypriot President Nikos Christodoulides, Mr. Modi laid out an ambitious canvas for the bilateral relationship, presenting Cyprus as an "investment gateway" to the European Union (EU). Cyprus currently holds the Presidency of the Council of the European Union.

India and Cyprus announced the elevation of their bilateral ties to the level of a "strategic partnership", and also formed a road map for defence cooperation. Cypriot officials said that Nicosia is interested in buying items from the Indian defence industry. "India-Cyprus relations are strong as well as futuristic. Our relationship is based on democracy and the rule of law. We respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India is totally committed to these principles and will remain so in the future," the Prime Minister said in a statement, after the two sides held delegation-level talks and sealed multiple agreements at Hyderabad House.

Prime Minister Narendra Modi with Cypriot President Nikos Christodoulides in New Delhi on Friday. SUSHIL KUMAR VERMA

Mr. Modi's reference to "sovereignty and territorial integrity" is being widely interpreted as support to Cyprus as it continues to deal with Northern Cyprus, which Turkey recognises as a separate state.

Bridge to the EU

In his remarks, the visiting President presented Cyprus-India ties as an entry point for India's wider relationship with the EU, with which New Delhi concluded a Free Trade Agreement earlier this year.

Following the talks, senior Cypriot officials said that Cyprus is eager to provide transhipment facilities for the global traffic of commodities and cargo that are affected by the U.S.-Israel war against Iran. To help remedy the current disruption in supply chains, Cyprus has started powering the IMEEC and has formed a 'Friends of IMEEC' grouping within the EU. "We had extensive discussions on IMEEC. We agree that we need to start the building blocks in order for IMEEC to be realised," a Cypriot official said. Direct flights will soon be launched between India and Cyprus, Cypriot officials said.

They also shared an ambitious plan to use the India-Cyprus relationship to energise the IMEEC project that will also restructure the security architecture of the eastern Mediterranean where Turkey is an active player because of its stakes in northern Cyprus.

According to a joint statement issued at the end of the visit, Mr. Modi and Mr. Christodoulides welcomed the signing of an MoU between the Cyprus Defence and Space Industries Cluster and the Society of Indian Defence Manufacturers. The two sides will intensify collaboration in cybersecurity, the maritime domain, and emerging technologies, it said.